

30 जून 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के आकार में 30.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2018-19 के ₹1,930.36 बिलियन की तुलना में 2019-20 में सकल कुल आय ₹1,496.72 बिलियन रही। पिछले वर्ष की आय में आकस्मिकता निधि से बेशी प्रावधान की ₹526.37 बिलियन प्रतिलेखन आय भी शामिल थी। इसको पिछले वर्ष की आय से निकालने के बाद की गई तुलना में 2019-20 की आय में सीमांत वृद्धि दिखती है। 2018-19 के ₹170.45 बिलियन की तुलना में बैंक का 2019-20 में व्यय ₹925.40 बिलियन रहा जिसमें आकस्मिकता निधि हेतु ₹736.15 बिलियन का जोखिम प्रावधान शामिल है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष ₹571.28 बिलियन रहा।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 तुलन-पत्र में ₹12,318.88 बिलियन अर्थात् 30.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹41,029.05 बिलियन था जो 30 जून 2020 को बढ़कर ₹53,347.93 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि के मुख्य कारण घरेलू और विदेशी निवेश में क्रमशः 18.40 प्रतिशत और 27.28 प्रतिशत की वृद्धि तथा ऋण तथा अग्रिम में 245.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी, स्वर्ण में 52.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना

थे। देयता पक्ष में हुई वृद्धि निर्गत नोटों, अन्य देयताओं और प्रावधानों तथा जमाराशियों में क्रमशः 21.52 प्रतिशत, 30.47 प्रतिशत और 53.72 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 28.75 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 71.25 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2019 को ये क्रमशः 28.03 प्रतिशत और 71.97 प्रतिशत थीं।

XII.3 ₹736.15 बिलियन प्रावधान किया गया और इसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गयी है।

2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
ए) आय	808.70	618.18	782.81	1,930.36	1,496.72
बी) कुल व्यय @	149.90#	311.55^	282.77&	170.45*	925.40**
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	658.80	306.63	500.04	1,759.91	571.32
डी) निधियों को अंतरण @@	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	658.76	306.59	500.00	1,759.87	571.28

@ : इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

: इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

^ : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

& : इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

* : एडीएफ में अंतरण के लिए ₹0.64 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

** : इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹736.15 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

@@ : पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹0.01 बिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

XII.4 वर्ष 2019-20 के लिए तैयार स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण

लेखांकन नीति संबंधी विवरण तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:-

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	2018-19	2019-20	आस्तियां	अनुसूची	2018-19	2019-20
पूंजी		0.05	0.05	बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.09	0.13
अन्य आरक्षित निधि	1	2.30	2.32	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	882.98	1,428.75
जमाराशियाँ	2	7,649.22	11,758.60	निवेश-विदेशी बैंकिंग विभाग	7	6,964.53	10,234.00
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	11,624.51	15,166.21	निवेश-घरेलू बैंकिंग विभाग	8	9,898.77	11,720.27
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	931.87	3,222.07
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	19.64	19.64
				अन्य आस्तियां	11	643.20	367.32
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां			
जारी किए गए नोट	4	21,687.97	26,355.75	सोने के सिक्के और बुलियन	6	792.04	1,131.46
				रुपये सिक्के		8.28	7.85
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	7	20,887.65	25,216.44
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
कुल देयताएं		41,029.05	53,347.93	कुल आस्तियां		41,029.05	53,347.93

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

**भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2020 को समाप्त वर्ष का आय विवरण**

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2018-19	2019-20
ब्याज	12	1,068.37	1,093.33
अन्य आय	13	861.99	403.39
कुल		1,930.36	1,496.72
व्यय			
नोटों का मुद्रण		48.11	43.78
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.88	0.87
एजेंसी प्रभार	14	39.10	38.76
कर्मचारी लागत		68.51	89.28
ब्याज		0.01	0.01
डाक और संचार प्रभार		1.03	1.17
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.22	0.20
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.26	1.36
मरम्मत और रखरखाव		0.98	0.88
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.05	0.06
विधिक प्रभार		0.17	0.09
विविध व्यय		7.97	10.71
मूल्यहास		1.50	2.06
प्रावधान		0.64	736.15
कुल		170.45	925.40
उपलब्ध शेष राशि		1,759.91	571.32
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		280.00	0.00
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		1,479.87	571.28

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

वार्षिक रिपोर्ट

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2018-19	2019-20
अनुसूची 1:	अन्य आरक्षित निधियाँ		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.28	0.29
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.02	2.03
	कुल	2.30	2.32
अनुसूची 2:	जमाराशियां		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.00
	(ii) राज्य सरकारें	0.42	0.43
	उप योग	1.43	1.43
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,129.26	4,376.17
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	39.98	52.08
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	90.29	71.38
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	24.91	24.72
	(v) अन्य बैंक	209.64	184.14
	उप योग	5,494.08	4,708.49
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप योग	0.00	0.00
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	46.38	45.49
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	257.47	331.14
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	19.05	16.80
(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2.13	23.47	
(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.38	3.52	
(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01	
(vii) अन्य	1,825.29	6,628.25	
उप योग	2,153.71	7,048.68	
कुल	7,649.22	11,758.60	
अनुसूची 3:	अन्य देयताएं और प्रावधान		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	1,963.44	2,640.34
	(ii) आस्तित विकास निधि (एडीएफ)	228.75	228.75
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	6,644.80	9,771.41
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)	157.35	538.34
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	494.76	934.15
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	13.04	0.00
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	59.25
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	22.81	26.00
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	206.10	256.39
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	1,759.87	571.28
	(xi) देय बिल	0.08	0.02
	(xii) विविध	133.51	140.28
कुल	11,624.51	15,166.21	
अनुसूची 4:	जारी नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.09	0.13
	(ii) संचलन में नोट	21,687.88	26,355.62
कुल	21,687.97	26,355.75	

संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

30 जून को एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को सीएफ के लिए प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को इसकी प्रतिप्रविष्टि की जाती है। आरएफसीए और पीएफसीवीए की शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर हुए क्रमशः लाभ या हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है। जहाँ एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, वहीं आरएफसीए तथा एसएए 'अन्य आस्तियों' के तहत दर्शाए जाते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार योग्य मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेनदेन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेनदेन के जरिए बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है और इन्हें दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर दर्शाया जाता है एवं इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों को माह के अंतिम कारोबारी दिवस को बाजार भाव पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)' में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में जमा शेष को आगामी लेखा वर्ष के लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-आरएस में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिकता निधि (सीएफ) पर प्रभारित किया जाता है और आगामी लेखा वर्ष के प्रथम कार्यदिवस को इस राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूतियों/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि, जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन भी दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्यन लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्यन लागत आधार पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियों को, जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों (यथा ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि) तथा जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेनदेन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/ रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रिपो लेनदेन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेनदेन को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है।

2.7 अचल आस्तियां

- (ए) कला तथा पेंटिंग्स एवं पूर्ण स्वामित्व वाले भूभाग, जो कि लागत मूल्य पर दर्शाए जाते हैं, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।
- (बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहीत तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास पूंजीकरण वाले महीने से आनुपातिक रूप में मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्ति की उपयोगिता अवधि के आधार पर निर्धारित की गयी दरों पर वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।
- (सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाली) पर मूल्यहास आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती करते हुए निम्नानुसार किया जाता है :

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन मूल्यहास की दर
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

- (डी) ₹0.10 मिलियन तक की लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से लाने-ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से लाने-ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत

किया जाता है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

- (ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।
- (एफ) मूल्यहास का प्रावधान, छमाही की समाप्ति पर मौजूद अचल आस्तियों की शेष राशि पर प्रति माह आनुपातिक आधार पर किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यहास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।
- (जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यहास :
- वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यहास पूर्णरूप से लेखा बही में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यहास की गणना मूल आस्ति की बची हुई उपयोगिता अवधि के आधार पर की जाती है; और
 - पहले से मौजूद ऐसी अचल आस्तियाँ, जिनका मूल्यहास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, उनके आधुनिकीकरण/ वृद्धि/ मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यहास पूर्णरूप से उसी वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।
- (एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

- 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

- ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।
- iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

- i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यहास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि तीस वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- ii. भवनों को हुई क्षति : क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यहास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रेप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक

हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रेप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

- ए. बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.5 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.5.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

XII.5.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा

किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को सीजीआरए में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

XII.5.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के अनुसार ₹0.10 बिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹0.01 बिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹0.29 बिलियन थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹0.50 बिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹0.01 बिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.03 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹0.01 बिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.5.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एकजम बैंक) और नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 53.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 के ₹7,649.22 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹11,758.60 बिलियन हो गयी।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2019 के ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.43 बिलियन थीं।

निवेश-घरेलू-बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2020 के अनुसार ₹676.09 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ ली गई स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखी गयी है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का ऋण और अग्रिम 30 जून 2019 के ₹265.31 बिलियन से घटकर 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य हो गए चूंकि केंद्र सरकार उस दिन अधिशेष में थी। जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2019 के ₹26.66 बिलियन की तुलना में बढ़कर 30 जून 2020 को ₹46.24 बिलियन हो गए।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :

इसमें मुख्यतः एलएएफ और एमएसएफ और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून

2019 की ₹572 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹2,855.77 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों के लिए रिपो के एवज में बकाया राशि में वृद्धि रही।

- नाबार्ड को ऋण और अग्रिम :

रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 की शून्य स्थिति से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹221.23 बिलियन हो गयी।

- अन्य को ऋण और अग्रिम :

इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता शामिल हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 की ₹67.90 बिलियन से 45.55 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹98.83 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण एनएचबी को ऋण और अग्रिम में वृद्धि थी।

vii) अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में निवेश

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक का, अपनी अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में कुल धारिता पिछले वर्ष के समान ₹19.64 बिलियन थी। इसका विवरण सारणी XII.6 में दिया गया है।

viii) अन्य आस्तियां

‘अन्य आस्तियों’ में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), उपचित आय, एसएए, आरएफसीए तथा विविध आस्तियों में धारित शेष होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण

सारणी XII.6: 2019-20 में अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में धारिताएं

अनुषंगी/सहायक संस्थाओं	(राशि ₹ बिलियन में)	30 जून 2020 तक प्रतिशत धारिता
1	2	3
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	100
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	0.50	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.30	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	0.34	100
कुल	19.64	

परियोजनाओं पर किए गए व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि शामिल हैं। अन्य आस्तियों के तहत शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹643.20 बिलियन थी जो 42.89 प्रतिशत घटकर 30 जून 2020 को ₹367.32 बिलियन रह गयी।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा की गयी है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे एसएए में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर प्रत्यावर्तित किया जाना है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार कोई भी बकाया संविदाएं नहीं हैं।

बी. वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

मौजूदा नीति के अनुसार वायदा संविदाओं को बाजार भाव पर अर्धवार्षिक आधार पर दर्शाया जाता है और इससे हुए निवल लाभ को एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। आरएफसीए शेष 30 जून 2019 की स्थिति ₹13.04 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य था।

XII.6.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश-विदेश-आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 661.41 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान के लिए रखा गया है (सारणी XII.4)। जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2019 को ₹792.04 बिलियन था, जो 42.85 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹1,131.46 बिलियन हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित निवेश-विदेश-आईडी 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹20,877.65 बिलियन थी, जो 20.72 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹25,216.44 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹8.28 बिलियन से 5.19 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹7.85 बिलियन रह गई।

XII.7 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)

XII.7.1 एफईआर में एफसीए, स्वर्ण, एसडीआर एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। विशेष आहरण अधिकार,

किया गया। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी प्रभार वर्ष 2019-20 में 0.76 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ ₹37.88 बिलियन रहा जबकि 2018-19 में यह ₹38.17 बिलियन रहा था। ₹0.29 बिलियन की मामूली गिरावट ई-कुबेर इंटीग्रेशन के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी लेनदेन प्रक्रिया और कोविड से उत्पन्न परिस्थिति के कारण संबंधित सरकारी लेनदेन में संभावित गिरावट के दोहरे प्रभाव के कारण हुई।

बी. *प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

रिजर्व बैंक द्वारा 2019-20 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹0.61 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2018-19 में यह ₹0.74 बिलियन रहा था। जुलाई 2019-जून 2020 की अवधि में जी-सेक उधार कार्यक्रम में बढ़ोतरी और अंतिम तिमाही में कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितता देखी गई। तथापि, इन घटनाओं के चलते प्रतिलाभ में होने वाली संभावित बढ़ोतरी वर्ष भर अनेक कारणों से काफी हद तक प्रभावित रही। पहली दो तिमाहियों के दौरान, आर्थिक स्थिति कम अस्थिरता के साथ स्थिर बनी रही। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में की गई कटौती और बाजार हस्तक्षेप के कारण प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहीं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार विवाद कम देखा गया। अंतिम तिमाही के दौरान, ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ), लॉन्ग टर्म रिपो

ऑपरेशंस (एलटीआरओ) और लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) के माध्यम से प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय यथा – नीतिगत दरों में कटौती और समय पर हस्तक्षेप के कारण पूरे प्रतिफल वक्र में प्रतिफलों में काफी नरमी देखी गई। इसे वैश्विक कारकों यथा- कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए समान उदार रुख का भी समर्थन मिला। इसके अतिरिक्त, सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने संबंधी उपायों की घोषणा के चलते बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहा। इसलिए, पूरे वर्ष घरेलू ऋण बाजार की स्थिति स्थिर बनी रही, जिससे ऐसी नौबत की संभावना घट गई जिससे प्रतिभूतियों को हामीदारी करने के लिए प्राथमिक व्यापारी पिछले वर्ष की तुलना में कम कमीशन की मांग करते।

सी. *विविध खर्च*

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत /बचत बॉन्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2018-19 के ₹0.02 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹0.06 बिलियन हो गया।

डी. *बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क*

वर्ष 2019-20 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2018-19 के ₹0.17 बिलियन से बढ़कर ₹0.21 बिलियन हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2019-20 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 22,388 मिलियन (एमपीसीएस) थी जो कि वर्ष 2018-19 (29,191 एमपीसीएस) की तुलना में 23.31 प्रतिशत कम है। इसलिए बैंक नोटों के मुद्रण पर व्यय 2019-20 में 9.00 प्रतिशत घटकर ₹43.78 बिलियन रह गया जबकि 2018-19 में यह ₹48.11 था।

v) प्रावधान

वर्ष 2019-20 में ₹736.15 बिलियन राशि का प्रावधान सीएफ के लिए किया गया।

vi) अन्य

अन्य व्यय 2018-19 के ₹14.08 बिलियन से 23.72 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹17.42 बिलियन हो गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं।

XII.10 आकस्मिक देयताएं

XII.10.1 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹11.68 बिलियन हो गईं। इसका मुख्य घटक यह है कि बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकाल्ड लायबिलिटी) 30 जून 2020 को ₹9.30

बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

XII.11 पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.11.1 प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹(-)0.01 बिलियन एवं ₹0.36 बिलियन थे।

XII.12 पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.12.1 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

XII.13 लेखापरीक्षक

XII.13.1 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2019-20 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी, मुंबई एवं मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स कोठारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स बंसल एंड कंपनी, एलएलपी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।